officers who are one level below the Board of Nationalised Banks, the CBI requires prior sanction of the Secretary of the administrative Ministry before initiating investigation. This is to prevent investigation into vexatious, frivolous and malicious complaints, which would demoralise officers at senior levels on the one hand and enable the CBI on the other to concentrate its attention on cases of serious nature.

अभ्यावेदनों/आवेदनों के संबंध में कार्यवाही न किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारी

2746. **श्री नागमणि:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय अधिकारियों को अभ्यावेदनों/ज्ञापनों एवं आवेदनों के संबंध में नियमों के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रहमण्यन): (क) से (ग) लोक शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वे लोक शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखें और किये गये निपटान की तिमाही रूप से समीक्षा करें। आवेदनों को तत्काल निपटाने और शिष्टाचार दिखाने तथा ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्य के निपटान में विलंबकारी तरीके अपनाएं और जानबूझकर विलंब करें, अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं। लोक शिकायतों की पावती भेजने/अंतिम रूप से उनका निपटान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में भी केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में प्रावधान किए गये हैं। इस संबंध में अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। इस बारे में कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित कोई आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

Termination of extension of Central Government Officers

2747. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answers to unstarred Questions 105 and 1345 given in the Rajya Sabha on the 21st November, 1996 and the 6th March, 1997, respectively, and state:

(a) whether Government propose to review the decision to grant extension to officers in Central Government Ministries/Departments and terminate extensions given to them; if not, the reasons therefor; and

(b) whether Government are contemplating to give extensions to the Officers of the rank of Joint Secretary and above who are going to superannuate in the near future; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) No, Sir. Extensions in service have been granted in the public interest.

(b) No, Sir.

CBI investigation into failure to apprehend Ottavio Quattrocchi

2748. SHRI ASHOK MITRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Bureau of Investigation would be asked to investigate into the reasons and circumstances leading to failure to apprehend or interrogate the italian citizen, Ottavio Quattrocchi, in July, 1993, despite disclosure of facts